

upon him that it would be necessary to take locational advantages so that both the countries can be benefited out of the agreements and we are having discussions further and I hope something would possibly be done.

श्री रामलाल राही : अध्यक्ष महोदय, श्री मन्त्री महोदय ने बताया है कि पाकिस्तान से साय-सब्जी आयात किया जाता है और रुई की गांठें आयात करने का फैसला किया गया है। सेंधा नमक, जिसे साहीरी नमक के नाम से जाना जाता है, इस मुल्क में पाकिस्तान से आता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सेंधा नमक का यहाँ आना बन्द हो गया है। उस नमक की हमारे देश में कमी है और इस लिए वह काफी महंगा है। क्या उसके आयात के बारे में पाकिस्तान से कोई सौदा हुआ है, अगर नहीं, तो क्या सरकार पाकिस्तान के साथ इस प्रकार का कोई सौदा करने का विचार कर रही है यथवा नहीं ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE :
Sir, we have not tried to have any bargain in respect of any individual commodity. But my objective is to expand the volume of trade between these two countries and a large number of items are there in which we are mutually interested and I have tried to identify those items so that we can take from them as also they can take from us. So far as cotton is concerned, I find that purchase of cotton from them would work out to be cheaper, convenient and advantageous to us. And in that I did not suggest to him that you are to take certain things from us because you can not expect that with every country you will have a balance of trade. With some countries you may have an adverse balance and with some you may have surplus. So, that way international trade goes on. Here, I have rather expressed my keenness to accommodate Pakistan's point of view in a better manner.

श्री राम लाल राही : मन्त्री महोदय ने सेंधा नमक के बारे में नहीं बताया है।

MR. SPEAKER : He has clearly stated.

Rise in prices of Controlled Cloth

*82. **SHRI RASHEED MASOOD :**
SHRI MANGAL RAM PREMI :
Will the Minister of **COMMERCE** be pleased to state :

(a) whether the prices of controlled cloth have been raised, despite Government allowing a higher subsidy to the producers;

(b) if so, the extent to which higher subsidy is allowed by Government to the producers;

(c) the reasons for the upward revision of the prices "Janata" Cloth; and

(d) its likely impact on the consumers?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) to (d) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) : Controlled cloth prices were fixed by Government in 1974 and Government was committed to pay a subsidy to the producers of controlled cloth which was equivalent to the difference between the price of controlled cloth and its cost of production. While the subsidy paid varied from time to time depending on the cost of production, the difference between price of controlled cloth and its cost of production had exceeded Rs. 3/- per sq. mt. on the basis of current cost. As against this, the subsidy entitlement under the revised scheme is Rs. 2/- per sq. mt. for sarces and dhoties

and Rs. 1.50 per sq. mt. for long cloth produced in the mill sector. It is envisaged that the entire requirement of controlled cloth from the mill sector will be produced by the NTC. The prices of controlled cloth have been increased as a result of the radical change in costs between 1974 and July 1981.

(c) and (d) : The price of janata cloth was re-fixed on the basis of costs input in 1977. In keeping with the change in costs, an increase of 15% has been allowed in selling prices from July 1981. This slight increase is likely to be easily absorbed by the consumers.

श्री रशीद मसूद : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अपने जबाब में बताया है कि कन्ट्रोल्ड क्लाय, जिसको कि गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत 15 पर्सेन्ट बढ़ाई है। मुझे अफसोस है कि उन्होंने इसको स्लाइट इन्क्रीज बताया है क्योंकि यह 15 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी इन लोगों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह 15 पर्सेन्ट की इन्क्रीज न करके अगर सरकार इसको भी सविस्तराईज करदे तो सरकार को कुल कितना एमाउन्ट बर्दाश्त करना पड़ेगा? और क्या सरकार यह सब्सिडी देने पर गौर करेगी?

[श्री रशीद मसूद :]

साहब - मसूद साहब ने अपने जवाब में बताया है कि कन्ट्रोल्ड क्लाय, जो कि गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत 15 पर्सेन्ट बढ़ाई है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह 15 पर्सेन्ट की इन्क्रीज न करके अगर सरकार इसको भी सविस्तराईज करदे तो सरकार को कुल कितना एमाउन्ट बर्दाश्त करना पड़ेगा? और क्या सरकार यह सब्सिडी देने पर गौर करेगी?

15 पर्सेन्ट की इन्क्रीज न करके अगर सरकार इसको भी सविस्तराईज करदे तो सरकार को कुल कितना एमाउन्ट बर्दाश्त करना पड़ेगा? और क्या सरकार यह सब्सिडी देने पर गौर करेगी? -]

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Sir, apart from 15 percent rise, I am already providing subsidy. And so far as the Handloom sector is concerned, I have increased the subsidy from Rs. 1.25 per metre to Rs. 1.50 per metre; and the total subsidy would be in the neighbourhood of Rs. 100/- crore.

For the controlled cloth of 650 million metres, 325 million metres is to be produced by the handloom and 325 million metres is to be produced by the N T. C. But in spite of this increased subsidy, we found unless we increase the price so far as the handloom sector is concerned, in the neighbourhood of 15% it would not be possible for the handloom weavers to get a remunerative price.

SHRI RASHEED MASOOD : But, Sir, simultaneously the Hon. Minister has increased the price of the cloth which has to be worn by the poor person for whom this cloth is produced. I want to know whether he will be in a position to subsidise those consumers?

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Sir, I am not in a position to increase the quantum of subsidy.

श्री रशीद मसूद : स्पीकर साहब, मैंने पिछले से पिछले साल भी इस सवाल को उठाया था तो जियाउर्रहमान अंसारी साहब जोकि कामर्स के स्टेट मिनिस्टर थे उन्होंने जवाब दिया था कि हम इस पर गौर कर रहे हैं लेकिन आज तक गौर नहीं हुआ। अब जो नयी पालिसी आई है उसमें भी बदकिस्मती से वही कमी रह गई है। 650 मिलियन मीटर कपड़ा कन्ट्रोल्ड क्लाय का बनाया है जिसमें साढ़े तीन सौ मिलियन मीटर कपड़ा हैंडलूम का होगा। कन्ट्रोल्ड क्लाय पर जो

सबसीडी सरकार की तरफ से दी जाती है वह मिल्स की बुकतलिफ रेट पर मिलती है - 2 रुपये और 1.50 रुपये जोकि पहले 75 पैसे और 1 रुपया थी—लेकिन हैडलूम को बहुत कम सबसीडी मिलती है। खुरशीद आलम खां साहब ने भी एलान किया था कि हैण्डलूम इण्डस्ट्री और स्मॉल स्केल इण्डस्ट्री को बढ़ाया जायेगा क्योंकि उनके साथ डिस्ट्रिबिनेशन होता है, मिल जो कपड़ा बना रही है उनको ज्यादा सबसीडी दी जाती है और हैण्डलूम इण्डस्ट्री को कम दी जाती है। क्या मिनिस्टर साहब इसपर गौर फरमाएंगे कि हैण्डलूम ओनर जो हाथ का कपड़ा बना रहे हैं उनको ज्यादा सहायता दी जाए ताकि वे भी मिलों के साथ कपीट कर सकें और यह 650 मिलियन मीटर कन्ट्रोल्ड क्लॉथ का ज्यादातर हिस्सा हैण्डलूम के लिए रिजर्व कर दिया जाए ?

[श्री रशोद नसरोद : अहमदाबाद]

साहब - मैंने पूछने से पूछने साल भी इस सवाल को अठाया था तो शो'अलरहमन अन्वारी साहब जो कि कामर्स के असेम्बली में थे उनसे ने जवाब दिया था कि हम इस पर गौर कर रहे हैं लेकिन अज तक गौर नहीं हुआ - जब जो नई पालिसी आती है उस में भी बदलसती से वही कमी दे दी जाती है - 400 मिलियन मीटर कपड़ा कन्ट्रोल्ड क्लॉथ का बनाना है जिस में साठे तहों से 400 मिलियन मीटर कपड़ा हैण्डलूम का होगा - कन्ट्रोल्ड क्लॉथ पर जो सबसीडी सरकार की तरफ से दी जाती है वह 90 पैसे है - इतना फर्क क्यों है, मिनिस्टर साहब ने इस सवाल को साफ नहीं किया ?

मिली है - 2 रुपये और 1.50 रुपये जो कि पहले 75 पैसे और 1 रुपया थी - खुरशीद आलम खां साहब ने भी एलान किया था कि हैण्डलूम इण्डस्ट्री और स्मॉल स्केल इण्डस्ट्री को बढ़ाया जायेगा क्योंकि उनके साथ डिस्ट्रिबिनेशन होता है, मिल जो कपड़ा बना रही है उनको ज्यादा सबसीडी दी जाती है और हैण्डलूम इण्डस्ट्री को कम दी जाती है। क्या मिनिस्टर साहब इसपर गौर फरमाएंगे कि हैण्डलूम ओनर जो हाथ का कपड़ा बना रहे हैं उनको ज्यादा सहायता दी जाए ताकि वे भी मिलों के साथ कपीट कर सकें और यह 650 मिलियन मीटर कन्ट्रोल्ड क्लॉथ का ज्यादातर हिस्सा हैण्डलूम के लिए रिजर्व कर दिया जाए ?

के साथ सबसीडी मिलती है - 2 रुपये और 1.50 रुपये जोकि पहले 75 पैसे और 1 रुपया थी—लेकिन हैडलूम को बहुत कम सबसीडी मिलती है। खुरशीद आलम खां साहब ने भी एलान किया था कि हैण्डलूम इण्डस्ट्री और स्मॉल स्केल इण्डस्ट्री को बढ़ाया जायेगा क्योंकि उनके साथ डिस्ट्रिबिनेशन होता है, मिल जो कपड़ा बना रही है उनको ज्यादा सबसीडी दी जाती है और हैण्डलूम इण्डस्ट्री को कम दी जाती है। क्या मिनिस्टर साहब इसपर गौर फरमाएंगे कि हैण्डलूम ओनर जो हाथ का कपड़ा बना रहे हैं उनको ज्यादा सहायता दी जाए ताकि वे भी मिलों के साथ कपीट कर सकें और यह 650 मिलियन मीटर कन्ट्रोल्ड क्लॉथ का ज्यादातर हिस्सा हैण्डलूम के लिए रिजर्व कर दिया जाए ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE :
Sir, I am not perhaps clear to the Hon. Member. I explained in reply to his first Supplementary that the scheme of the controlled cloth is that total production would be 650 million metres. 325 million metres, i. e. 50% will be produced in the handloom sector and subsidy, which will be given to the handloom sector, is Rs. 1.50 per metre against 325 million metres to be produced. Rest, 325 million metres will be produced in the N. T. C. To some extent, we have provided subsidies. About the question of quantum into our judgement we cannot increase the subsidy any more.

श्री अशफाक हुसैन : कन्ट्रोल का कपड़ा और जनता कपड़ा हैडलूम और एन० टी० सी० में बांटा गया है। जैसाकि अभी रशोद मसूद साहब ने सवाल किया था कि हैडलूम के लिये सबसीडी 1 रुपये 50 पैसे है और एन० टी० सी० में प्रोड्यूस होने वाले माल के लिये 1 रुपये 90 पैसे है - इतना फर्क क्यों है, मिनिस्टर साहब ने इस सवाल को साफ नहीं किया ?

इसी के साथ एक सवाल मैं यह पूछना चाहता हूँ कि एक ही काउन्ट का कपड़ा जो एन० टी० सी० में तैयार होता है और उसी काउन्ट का कपड़ा जो हैण्डलूम में तैयार होता है, दोनों के दामों में बहुत फर्क है। हैण्डलूम को उस का कम पैसा मिलता है, एन० टी० सी० को ज्यादा मिलता है। क्या यह जात है कि चूंकि कार्पोरेशन

घाटे में चल रही है इसलिये उसको ज्यादा पैसा दिया जाता है। हैण्डलूम जो गरीबों की रोजी और रोटी का जरिया है उन से जबरबस्ती छन की लागत से कम दाम पर कपड़ा लिया जाता है। मैं इस के बारे में मंत्री जी से बजाहत चाहता हूं।

SHRI PRANAB MUKHERJEE :
As I have already mentioned, mainly we have reduced the production of controlled cloth to three varieties, viz. dhoties, sarees and long cloth. NTC will produce dhoties, sarees and long cloth. The handloom sector will produce dhoties and sarees. If the Hon. Member is interested in figures, I can give him the production figures also. In the handloom sector, the total production of sarees would be 215 million metres and dhoties would be 110 million metres—which totals up to 325 million metres. With regard to subsidies, as I have already mentioned, the question is whether we will allow some increase in the price.

Hon. Members would appreciate that the price of controlled cloth was fixed in 1974 ; and thereafter, we did not revise the price of controlled cloth. Therefore, it was thought that even if we are to provide subsidy it would be for the Finance Minister to take it from everybody's pocket and to disburse it among certain sections. That way, it does not help the economy of the community as a whole. Whether it is NTC or handloom, after all it is coming neither from his pocket, nor from my pocket. It is coming from everybody's pocket. Therefore, we thought: "Let us keep the subsidy in absolute terms to about Rs. 100 crores. And for the rest, let it be reflected partly in the increased price."

श्री डी. पी. यादव : अध्यक्ष जी, जो सब्सीडी देने की बात और गरीबों के बीच सस्ता कपड़ा बाँटने की बात कही जाती है, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात

लाना चाहता हूं कि जो 100 करोड़ खर्चा दिया जाता है उसमें से मुश्किल से 20 करोड़ रुपया गरीबों के पास पहुँच पाता है, 80 करोड़ रुपया मेरे हिसाब से एन० टी० सी० में बरबाद हो रहा है। आप किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में विदलेषण टीम भेजिये और देखिये कि डिस्ट्रिब्यूशन का क्या सिस्टम है और प्रोडक्शन का क्या सिस्टम है, दोनों सिस्टम को कम्पेअर करने के बाद पता चल जायगा कि एन० टी० सी० के डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्यूफैक्चरिंग प्रोसेज में कितना अफ़्टाचार है। मैं चाहूँगा कि सरकार इस के पिछले दो-तीन सालों के कामों का सैम्पल के तौर पर इन्टन्सिव सर्वे कराये।

SHRI PRANAB MUKHERJEE :
So far as the quantum of subsidy is concerned, I have given the rate. I have given the total figure. I am not strong in arithmetic. The Hon. Member can multiply 325 million metres by Re. 1-50 ; and he will get the figure.

So far as corruption and other matters of NTC are concerned, we are making a constant exercise. But one point has to be kept in mind : even to-day, Hon. Members would appreciate that every day I get letters at least from 2 or 3 MPs to take over some junk, and to manage them. Therefore, it would not perhaps be correct to say, when you ask the NTC to take over a unit to fulfil your social obligation to keep some people in employment, and at the same time you expect that they would be commercially and economically strong enough. Perhaps these two ends we cannot meet. But in regard to corruption and other matters, if the Hon. member has any specific point, definitely I would like to go into it.

श्री सोमजीभाई डामोर : अध्यक्ष महोदय, इतनी सब्सीडी और इतना कपड़ा

बनते हुए, जनता को सस्ता कपड़ा नहीं मिलता है और इस में बहुत घोटाला होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि सही दाम पर जनता को कपड़ा मिले, इस के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE :
So far as distribution is concerned, unfortunately, I am not in a position to say anything, as I told you ; it is produced and after that, it is distributed through the State agencies and cooperative sector.

**केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को
मंहगाई भत्ते का भुगतान**

७८३. श्री रामावतार शास्त्री :

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्य सूचकांक निरंतर बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मूल्य सूचकांक में हुई इस वृद्धि के परिणाम-स्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया है ;

(घ) यदि हाँ, तो मंहगाई भत्ते की कितनी किश्तें सरकार द्वारा देय हो गई हैं; और

(ङ) सरकार का विचार कब तक उनका भुगतान करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वाइ सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हाँ।

(ख) जून 1981 के लिए लेबर ब्यूरो, शिमला से प्राप्त नवीनतम सूचकांक 439 है जून, 1981 सहित पिछले 12 महीने का सूचकांक औसत 413.84 है।

(ग) से (ङ) : केन्द्रीय सरकारी कर्म-चारियों को मंहगाई भत्ते की पिछली किश्त उस समय मंजूर की गई थी जब 12 महीने का सूचकांक औसत 392 हो गया था। मार्च, 1981 तथा मई, 1981 के अन्त में सूचकांक औसत में 8 अंकों की वृद्धि होने के परिणाम-स्वरूप 1-4-81 तथा 1-6-81 से मंहगाई भत्ते की दो और किश्तें विचार किये जाने योग्य हो गई हैं। इन किश्तों की अदायगी का प्रश्न सरकार के ध्यान में है। चूंकि ऐसी अदायगी पर, देश की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से विचार किया जाना होता है, इसलिए इस मामले में निर्णय लेने में स्वभावतः कुछ समय लग सकता है।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : आपने किया है, इसलिए मानना ही पड़ेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, कीमतें शतान की आंत की तरह बढ़ती जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह नया मुद्दा बरा बरा निकाला है आप ने।

श्री रामावतार शास्त्री : आप सुन लीजिए। मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उसके अनुसार जून, 1981 में सूचकांक 439 आ गया और 12 महीने का औसत सूचकांक 413.84 था। इस से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कीमतें कितनी बढ़ती जा रही हैं। मेरे पास बहुत सारी फीगर्स हैं लेकिन वक्त कम है, इसलिए मैं उन को नहीं बताना चाहता, पर यह कहना चाहता हूँ कि आप हर साल सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किश्तें देते जा रहे हैं। सन् 1980